भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4175

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

लोवर सुबनसरी जल विद्युत परियोजना

4175. श्री पल्लव लोचन दासः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जल विद्युत परियोजना से जुड़े सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में लोवर सुबनसरी जल विद्युत परियोजना (एलएसएचईपी) से संबंधित राज्य समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विद्युत परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) पूरी परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और परियोजना में विलंब के कारण कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना के लिए असम राज्य सरकार द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है।

तथापि, परियोजना के सुरक्षा पहलुओं तथा डाउनस्ट्रीम प्रभाव की जांच करने के लिए भारत सरकार और एनएचपीसी द्वारा समय-समय पर विभिन्न तकनीकी समितियां/समूहों जैसे विशेषज्ञ समूह (ईजी), तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी), संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी), बांध डिजाइन समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) तथा परियोजना निगरानी समिति (पीओसी) गठित की गई थी। इसी दौरान, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष दो याचिकाएं दायर की गई थीं। माननीय एनजीटी ने एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने तथा रख-रखाव के लिए तात्कालिक स्वरूप के कार्यों एवं जनसुरक्षा प्रयोजन को छोड़कर परियोजना का निर्माण कार्य बंद करने के लिए एमओईएफएंडसीसी को निर्देश दिए। यह विशेषज्ञ समिति एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिनांक 27.11.2017 को गठित की गई थी। समिति ने 26.03.2019 को एमओईएफएंडसीसी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) द्वारा किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए माननीय एनजीटी के अंतिम आदेश के अध्यधीन सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। यह मामला माननीय एनजीटी में अब भी न्यायाधीन है।

(ग) : परियोजना कार्य पुनःआरंभ होने के पश्चात 4 वर्ष के भीतर चालू किए जाने की संभावना है।

(घ) : वर्ष 2003 में परियोजना के लिए 6,285 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2002 का मूल्य स्तर) के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था। परियोजना की अनुमानित संशोधित लागत 20850.67 करोड़ रुपए (अप्रैल, 2019 का मूल्य स्तर) है।

******